

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा

राजीव कुमार, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग,
एस.एस. (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Corresponding Author

राजीव कुमार, (Ph.D.), समाजशास्त्र विभाग,
एस.एस. (पी.जी.) कॉलेज,
शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/08/2022

Revised on : -----

Accepted on : 13/08/2022

Plagiarism : 00% on 08/08/2022



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा डॉ. राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.एस. (पी.जी.) कॉलेज, शाहजहांपुर। शोध सार 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शारीरिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर नयी शिक्षा नीति लायी गयी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस नीति से शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारत को दिखाएगी। इस नीति में उच्च शिक्षा के ढाँचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षा में लचीलापन और स्वायत्तता महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इन बदलावों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में जीवंतता लाने का प्रयास किया गया है। नयी शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम में मॉल्टिपल एंट्री एंड एकिजट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों को छात्र कई सर्वे पर छोड़ सकते और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावना शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की जीवन पर्यन्त चलने वाली क्रिया। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। लेकिन यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को देखें तो यह किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सोशल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसकी अन्तनिर्हित क्षमताओं का प्रकटीकरण और प्रस्फुटन होता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा ही मानव

शोध सार

21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर नयी शिक्षा नीति लायी गयी है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। इस नीति से शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारत को दिखाएगी। इस नीति में उच्च शिक्षा के ढाँचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षा में लचीलापन और स्वायत्तता महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इन बदलावों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में जीवंतता लाने का प्रयास किया गया है। नयी शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम में मॉल्टिपल एंट्री एंड एकिजट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों को छात्र कई सर्वे पर छोड़ सकते और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावना शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की जीवन

मुख्य शब्द

नई शिक्षा नीति, समाज, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी.

प्रस्तावना

शिक्षा का अर्थ है सीखने एवं सिखाने की जीवन पर्यन्त चलने वाली क्रिया। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। लेकिन यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ को देखें तो यह किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सोशल सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक गुणों और उसकी अन्तनिर्हित क्षमताओं का प्रकटीकरण और प्रस्फुटन होता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला-कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा ही मानव

विकास का मूल साधन है। शिक्षा ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण एवं उसका नैतिक विकास करती है तथा व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार करने का काम करती है। मानव जीवन को सजाने व संवारने में शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है।

नयी शिक्षा नीति

भारतीय समाज व्यवहार और विश्वास के मजबूत स्तंभों पर खड़ा एक ऐसा तंत्र रहा है जिसकी मुख्य धारा में ज्ञान, दर्शन, और विज्ञान तीनों का समन्वय रहा है रिन्टन (2020)¹ प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बहुत प्रभाव रहा है। वैशिक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए—नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए (NEP2020)² परिहार (2020)³ बताते हैं कि नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य ही शिक्षा की ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें भारतीय परम्पराओं और मूल्यों को जगह मिले। शिक्षा प्रणाली में इण्डिया की जगह भारत की झलक मिले। इसमें परम्परागत प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान तक की विरासत को शामिल किया गया है।

नयी शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 प्रतिशत भाग के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। धोत्रे (2020)⁴ के अनुसार आखिरी शिक्षा नीति 1986 के बाद के 34 वर्षों में विश्व अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर से गुजरा है। तकनीकी विकास के कारण विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं जिनसे जाति, वर्ग, संस्कृति, स्त्री—पुरुष, भौगोलिक दूरियों जैसे भेदभाव की अनेक दीवारें काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी हैं। इससे लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं जोरदार तरीके से जाग चुकी हैं।

यह नीति बहुआयामी तथा समग्र होने के साथ ही व्यवसायिक भी है और लचीली भी। यह शिक्षा नीति किताबी ज्ञान के बजाय कौशल विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती है। सिंह (2020)⁵ वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा खुलने के बाद तीव्र आर्थिक विकास ने ज्ञान और विशेषज्ञातापूर्ण कौशल की मांग काफी बढ़ा दी है। आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ होने के ढाई दशकों के दौरान हमारी शिक्षा प्रणाली में लंबे समय से व्यापक कमियों और विकास की आकांक्षा में आतुर भारत की छटपटाहट को दूर करने के लिए कोई विस्तृत राष्ट्रीय परिकल्पना सामने नहीं आ पायी थी। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राथमिकता दी है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 Read to Learn के स्थान पर Learn to Read पर अधिक फोकस करती है। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैशिक दृष्टिकोण के साथ भारत केंद्रित है। यह मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवन—शैली तथा वैशिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। यह भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होने के साथ—साथ, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन, पुनर्स्थापन एवं प्रसार पर जोर देती है। यह विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान करती है। जिससे यह भारत को एक समर्थ, गौरवशाली और आत्मनिर्भर बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सके। सिंह (2021)⁶ नयी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ—साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। विद्यार्थियों को एकीकृत किया जाना चाहिए, अर्थात् उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। रावत (2022)⁷ लिखते हैं कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नयी शिक्षा नीति एक अच्छी नीति है, 21वीं सदी भारत की आवश्यकता और सतत विकास लक्ष्यों के

अनुरूप शिक्षा को समतामूलक, समावेशी, लचीला बहु-विषयक बनाने की संकल्पना को साकार करती है। हालौंकि इसके सुचारू क्रियान्वयन से ही इसका आदर्श रूप भारत की शिक्षा व्यवस्था और प्रगति में परिवर्तित हो सकेगा।

नयी शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावानात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास आवश्यक है (NEP2020)।⁸ शिक्षा नीति का उद्देश्य नयी शिक्षा प्रौद्यौगिकी को अपनाना और कौशल विकसित कर नए विषय सीखना है। शिक्षा नीति में प्रौद्यौगिकी के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह डिजिटल बुनियादी ढँचे के उचित समर्थन और वर्तमान डिजिटल अंतर को पाठने के साथ ऑनलाइन सीखने पर जोर देती है (2021)।⁹

उच्च शिक्षा

सामाजिक स्तर पर, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक रूप से जागरुक, जानकार और सक्षम बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके, और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त समाधानों को ढूँढ़कर लागू कर सके। उच्च शिक्षा देश में ज्ञान निर्माण और नवाचार का आधार भी बनती है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य रोजगार सृजन ही नहीं है बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुड़े हुए सहकारी समुदायों के साथ एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है (NEP2020)।¹⁰ उच्च शिक्षा के बारे में इस नीति का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के समूहों को नॉलेज हबों में परिवर्तित करके उच्च शिक्षा में विखण्डन को रोकना है। इस नीति में न केवल वर्तमान युवा पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखा गया है बल्कि आने वाली पीढ़ी की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। उच्च शिक्षा में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। 34 वर्षों बाद यह शिक्षा नीति आयी है जो शोधपरक, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है। सरकार का ऐसा प्रयास है कि तेजी से बदलते सामाजिक आर्थिक वैशिक परिवेश में देश के युवाओं को सक्षम बनाया जाए।

धोत्रे (2020)¹¹ बताते हैं कि उच्च शिक्षा के सरोकार बड़े विविधतापूर्ण और जटिल हैं। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के मार्ग में बाधा डालने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जैसे: विषयों के बीच कठोर विभाजन रेखाएं, अध्यापकों की सीमित संख्या, स्वायत्तता की कमी, उच्च कोटि के और प्रासंगिक अनुसंधान की कमी और कमजोर संरथागत अभिशासन। नयी नीति विद्यार्थियों को इस बात की आजादी देती है कि वे क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं। अब कोई विद्यार्थी चाहे तो गणित के साथ संस्कृत और भौतिक विज्ञान के साथ संगीत पढ़ सकता है। पुरानी प्रणाली में सकायों के बीच विभाजन रेखाएं इतनी मजबूत होती थीं कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच कोई औपचारिक या संरथागत संपर्क संभव नहीं था। इससे व्यक्ति का स्वस्थ विकास संभव नहीं हो पाता था। नयी नीति में सभी विषयों को आपस में समन्वित करने का प्रयास किया गया है ताकि समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए आवश्यक नैतिकता और विश्वसनीयता के स्तरों में सुधार को सुनिश्चित करने और इसके द्वारा एक सफल विद्यालयी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्रणाली को उन निम्न स्तरीय और बेकार अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ उल्लंघन के लिए एक वर्ष का समय दिए जाने के पश्चात कठोर कार्यवाही का अधिकार होगा जो बुनियादी शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष 2030 तक, केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहु-विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।

(NEP2020) ¹² सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैकबोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियाँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण तथा परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढँचे और सुविधाओं से युक्त होंगे। प्रत्येक कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की पहुँच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।

उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याएँ:

- खण्डित उच्चतर शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र।
- संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल।
- विषयों का कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना।
- सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ते हैं।
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता।
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी-समीक्षा शोध नियमों की कमी।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव।
- रोजगार परक कौशल का अभाव।
- संसाधनों की कमी—UGC के बजट का लगभग 65 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को 35 प्रतिशत ही मिलता है।

नयी शिक्षा नीति में इस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तनों की बात की गयी है। इस नीति में उच्च शिक्षा के ढँचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। बहु-विषयक शिक्षा, शिक्षा में लचीलापन और स्वायत्तता महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इन बदलावों के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में जीवंतता लाने का प्रयास किया गया है। विभिन्न विषयों के बीच खींची गयी सीमा रेखा को पाटने का प्रयास किया गया है। पाठ्यक्रमों को क्रिटिकल आधारित बना दिया गया है साथ ही उनमें प्रवेश लेने और छोड़ने के प्रावधानों को आसान बना दिया गया है। शिक्षा नीति का केन्द्र बिन्दु उच्च शिक्षा में बिखराव को रोकना है। रावत (2022)¹³ बताते हैं कि जिस प्रकार यह शिक्षा नीति शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, उसमें नवाचार करने, अनुसंधान के क्षेत्र को नए आयाम तक पहुँचाने व बहु-विषयक पद्धति को अपनाने से लेकर डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा स्तर तक सार्वभौमिक करने की बात करती है जो व्यवहारिक रूप से आसान नहीं होगा।

उच्च शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन

चंद्राकर (2022)¹⁴ बताती हैं कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जहाँ कुछ खामियाँ हैं तो वहीं नयी तकनीकों, आसान उपलब्धता, स्कूल-कॉलेजों की संख्या में वृद्धि ने शिक्षा प्राप्त करना आसान बना दिया है। आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थान शिक्षा को व्यवसाय न बनाकर जिम्मेदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाएं तथा शिक्षा के प्रति जागरूक करें।

- ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु-विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहाँ प्रत्येक जिले में या उसके आस-पास कम से और पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे ही हों, जो स्थानीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों।
- संकाय और संस्थागत स्वायत्तता की ओर बढ़ना।

- नयी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नयी शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टिप्ल एंट्री एंड एकिजट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों को छात्र कई स्तरों पर छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा (एक वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एक 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' दिया जायेगा, ताकि अलग—अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नयी शिक्षा नीति के तहत 'एम. फिल.' कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।
- नयी शिक्षा नीति के तहत देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commission of India-HECI) की परिकल्पना की गयी है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगारप्रक बनाना।
- वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज—कोर्स निर्मित करना।
- आकाँक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जायेगा।

निष्कर्ष

नयी शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था में नवीन परिवर्तनों को लेकर आयी है। नयी नीति विद्यार्थियों को इस बात की आजादी देती है कि वे क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं और कब सीखना चाहते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ—साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करना है। यह नीति युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि को भी ध्यान में रखती है। नयी शिक्षा नीति की सफलता इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर है।

संदर्भ सूची

1. रिन्टन, एस. के. एवं नाहाक, फ. मो. (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं मीडिया साक्षरता। ज्ञान गरिमा सिंधु पत्रिका, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अंक 72, अक्टूबर—दिसंवर, पृ.101.
2. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 4—5.
3. परिहार, प्रेम. (2020). नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ। *International Journal of Applied Research, IJAR* 2020; 6 (9): 109-111. <http://www.allresearchjournal.com> पृ.110.
4. धोत्रे, संजय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। योजना पत्रिका, सूचना भवन प्रकाशन, नयी दिल्ली, अंक सितंबर, पृ. 6—10.
5. सिंह, नरेन्द्र. (2020). नयी शिक्षा नीति 2020: सामाजिक समावेशन का दस्तावेज। National Education Policy 2020: Conspectus, Book, Mahatma Gandhi Central Univ. Publication, Champaran, Bihar. पृ. 69.

6. सिंह, कृष्ण कुमार. (2021). वर्तमान भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उपादेयता। *IJARMS Journal* (On line), फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, अंक 4, पृ. 2.
7. रावत, अरविन्द. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समतामूलक और समावेशी शिक्षा क्रियान्वयन में अध्यापक शिक्षा की चुनौतियाँ, असोधवार्ता जर्नल, अदिति प्रकाशन, रायपुर छत्तीसगढ़, अंक 3, दिसंबर-फरवरी, पृ. 60.
8. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ. 4.
9. (2021). नयी शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी पर जोर। नयी दुनिया समाचार पत्र, इंदौर प्रकाशन, दिसंबर 26, पृ. 5.
10. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 53.
11. धोत्रे, संजय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। योजना पत्रिका, सूचना भवन प्रकाशन, नयी दिल्ली, अंक सितंबर, पृ. 8-9.
12. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार पृ. 64-68.
13. रावत, अरविन्द. (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समग्र विश्लेषण। शोध समागम जर्नल (ऑनलाइन), अदिति प्रकाशन, रायपुर छत्तीसगढ़, वर्ष 05, अंक 01, जनवरी-मार्च, पृ. 234-238.
14. चंद्राकर, क्षमा. (2022). भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था। शोध समागम जर्नल (ऑनलाइन), अदिति प्रकाशन, रायपुर छत्तीसगढ़, वर्ष 05, अंक 02, अप्रैल-जून, पृ. 579-582.
